

## विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की सुरक्षा

यह एडटिलेरियल 07/03/2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "A Safety Net for Students Abroad" लेख पर आधारित है। इसमें विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की सुरक्षा संबंधी आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

### संदर्भ

भारतीय छात्रों का अध्ययन के लिये विदेश जाना कोई नई परिधिटना नहीं है। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों की कमी और मांग-आपूर्ति अंतराल के कारण लंबे समय से कई भारतीय परिवार अपने बच्चों को अध्ययन हेतु विदेश भेजने के लिये विश्व होते रहे हैं। लेकिन हाल की दो घटनाओं कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूस के आकर्षण ने विदेशों में अध्ययनरत ऐसे छात्रों को विश्व रूप से सुरक्षियों में ला दिया है। जब तक भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनेगी, उनका विदेश जाना जारी रहेगा। भारतीय संस्थानों को प्रौद्योगिकी, चकितिसा और अन्य विषयों सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों के समक्ष अधिकाधिक विकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

### वर्तमान परिवेश

- वर्तमान में 7,70,000 भारतीय छात्र विदेशों में अध्ययनरत हैं, जो वर्ष 2016 में 4,40,000 छात्रों की तुलना में 20% वृद्धि को इंगति करता है। दूसरी ओर विदेशों में शिक्षा की मांग की तुलना में घरेलू क्षेत्र में वृद्धि केवल 3% रही है।
- विश्व में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर रहा है। महामारी की शुरुआत से पहले विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्र विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में 24 बिलियन डॉलर का वयय कर रहे थे, जो कभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है।
  - वर्ष 2024 तक विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्रों की संख्या बढ़कर लगभग 1.8 मिलियन हो जाने का अनुमान है जब भारतीय छात्र भारत से बाहर लगभग 80 बिलियन डॉलर खरच कर रहे होंगे।
- मेडिकिल की डिग्री हासिल करने के लिये भारतीय छात्र लगभग तीन दशकों से रूस, चीन, यूक्रेन, करिगसितान, कज़ाखस्तान और फलीपीस का रुख करते रहे हैं।
- भारत की पूरव विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को देश का 'बरांड एंबेसडर' पुकारा था। भारत और ब्राटिन के प्रधानमंत्री ने ब्राटिन में रह रहे भारतीयों को दोनों देशों के बीच का 'living Bridge' या 'जीवंत सेतु' कहा था।
  - भारतीय प्रवासियों (Indian Diaspora) का वृहत लाभ 'सॉफ्ट पावर', 'ज्ञान हस्तांतरण' (Knowledge Transfer) और भारत आने वाले धन वितरण (Remittances) के रूप में प्राप्त होता है।

### शिक्षा के लिये विदेश पलायन के मुख्य कारण

- जहाँ भारत की आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और दुनिया के शीर्ष 100 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, ऐसे में स्वाभाविक है कि भारतवाकांक्षी छात्र शिक्षा हेतु विदेश का रुख करेंगे।
- मेडिकिल डिग्री के विशेष संदर्भ में भारत के नजीबी मेडिकिल कॉलेजों में एम्बीबीएस सीट के लिये भुगतान की तुलना में विदेशों में रहने और शिक्षण शुल्क पर होने वाला खरच कहीं अधिक वहनीय है।
- भारत में उपलब्ध एम्बीबीएस सीटों की तुलना में एम्बीबीएस उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। राष्ट्रीय चकितिसा आयोग (NMC) के अँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 में देश में कुल 596 मेडिकिल कॉलेज थे, जहाँ एम्बीबीएस सीटों की संख्या 88,120 थी।

### छात्रों के समक्ष हाल में उत्पन्न हुआ संकट

- वर्तमान में जारी रूस-यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन में अध्ययनरत दो भारतीय छात्रों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले सामने आए हैं, जिनमें एक गोलाबारी का शकिर हुआ जबकि दूसरा हृदयाघात से अपनी जान गंवा बैठा।
  - यद्यपि बाह्य सशस्त्र आक्रमण के बीच यूक्रेन में अराजकता की स्थिति है, यह परिवेश गंभीर हस्तक्षेप की आवश्यकता रखता है।

- अनुमान है कि लगभग 20,000 भारतीय छात्र यूक्सेन में फैसे हुए थे।
- हाल ही में कनाडा में तीन कॉलेजों के अचानक बंद हो जाने से लगभग 2,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्र (जिनमें मुख्य रूप से भारतीय छात्र शामिल थे) प्रभावित हुए हैं।
  - आरोपों के अनुसार अब दिवालिया घोषित हो चुके इन कॉलेजों ने शक्तिशाली के रूप में छात्रों से लाखों रुपए प्राप्त किए थे और अब इन छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
  - महामारी के दौरान ऐसी ही एक घटना सामने आई थी जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने कॉलेज परसिरों में अध्ययन हेतु नामांकित हजारों भारतीय छात्रों के लिये अपनी सीमाएँ बंद कर दी थी।

## आगे की राह

- **मेजबान देशों की भूमिका:** विदेशों में अध्ययनरत भारतीय छात्र उन देशों में न केवल उच्च शिक्षा के उपभोक्ता हैं, बल्कि उनके मेहमान भी हैं। इस दृष्टिकोण से भारत के लिये यह स्वाभाविक ही होगा कि विह विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा हेतु मेजबान देशों द्वारा इसका उत्तरदायतिव ग्रहण करना सुनिश्चित कराए।
- **अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के माध्यम से सुरक्षा जाल:** भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये तत्परता से एक सुरक्षा जाल या 'सेफ्टी नेट' तैयार करना चाहिये। संकट और आकस्मिकताओं के समय भारतीय छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु मेजबान देशों को बाध्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को सर्वोपरिमहत्त्व दिया जाना चाहिये।
  - वर्तमान में यूक्से और ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही व्यापार समझौता वार्ताएँ एक बड़ा अवसर प्रदान करती हैं कि भारत इस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़े।
- **छात्र बीमा योजनाएँ:** लोकप्रिय धारणा के विपरीत विदेशों में अध्ययनरत छात्रों का एक बड़ा भाग समृद्ध परिवारों से संबंधित नहीं होता और वे प्रायः अपनी शिक्षा के वित्तीयों के लिये महंगे ऋण का सहारा लेते हैं।
  - बेहतर अवसर और भविष्य को सुरक्षित करने की आकांक्षा उन्हें कठनियों की ओर धकेल सकती है।
  - विदेशी सरकार के साथ समझौतों में एक अनावश्यक छात्र बीमा योजना के साथ-साथ विदेशों में छात्रों के कल्याण का उत्तरदायतिव मेजबान देश को सौंपने जैसी शर्तें शामिल की जानी चाहिये ताकि मेजबान देश में उल्लेखनीय राशि विद्यय करने वाले इन छात्रों के हतों की रक्षा की जा सके।
- **सरकारी मेडिकिल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि करना:** यदि पहुँच और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तो सरकारी मेडिकिल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि करना देश के लिये लाभप्रद होगा।
  - केवल नजी उद्यम का सहारा लेने से यह संभव नहीं होगा, बलकि राज्य और केंद्र सरकार जिला मुख्यालय अस्पतालों का उपयोग कर, आधारभूत संरचना का विस्तार कर और अधिक मेडिकिल कॉलेजों (नीति आयोग की अनुशंसा के अनुरूप) की स्थापना कर सकती है।
  - इस प्रकार, नमिन एवं मध्यम सामाजिक-आरथकि स्तर के बे छात्र भी लाभान्वति होंगे जो अन्यथा मेडिकिल सीटों तक पहुँच नहीं बना पाते हैं।
- **उच्च शिक्षा में अधिक नविश:** भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाने के लिये उच्च शिक्षा, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास में नविश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।
  - उच्च गुणवत्तापूरण अवसंरचना एवं नवाचार पारिंतर के निर्माण के लिये प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को वित्त प्रदान करने हेतु उच्च शिक्षा वित्तीयों (Higher Education Finance Agency- HEFA) का गठन एक स्वागतयोग्य कदम है।
  - इसके साथ ही, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परसिर स्थापित करने की अनुमति देने से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में विदेशी धन का प्रवाह बढ़ेगा और भारत से 'प्रताभि के पलायन' या 'ब्रेन ड्रेन' (Brain Drain) में कमी आएगी।

**अभ्यास प्रश्न:** देश के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्ति में भारतीय छात्रों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजायि और उन कदमों से संबंधित सुझाव दीजयि जो भारत में उच्च शिक्षा के लिये एक बेहतर पारिंतर के विकास हेतु उठाए जा सकते हैं।